<u>आरक्षित निर्णय</u>

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ,नैनीताल

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश श्री संजय कुमार मिश्रा

और

न्यायमूर्ति श्री रमेश चंद्र खुल्बे

आपराधिक अपील संख्या 17/2017

आरक्षित: 21.04.2022

वितरित: 18.05.2022

हिदायत अली. ...... अपीलकर्ता

बनाम

उत्तराखण्ड राज्य. ……प्रतिवादी

अपीलकर्ता के अधिवक्ता: श्री सज्जाद अहमद, एलडी अधिवक्ता

प्रतिवादी के वकील: श्री जे.एस. विर्क, एलडी। डी०ए०जी।

पक्षों को सुनने के बाद, माननीय न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया:

<u>निर्णय</u>: (श्री न्यायमूर्ति रमेश चंद्र खुल्बे)

यह आपराधिक अपील द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश रुड़की, जिला हरिद्वार की अदालत द्वारा वर्ष 2014 के सत्र परीक्षण संख्या 44, "राज्य बनाम हिदायत अली" में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 03.12.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसमें अपीलकर्ता को दोषी ठहराया गया है। आईपीसी की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए ट्रायल कोर्ट द्वारा और उसे 5000 / - रुपये के जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और उसे भुगतान करने में चूक करने पर आरोपी को आगे तीन महीने का कठोर कारावास और सजा भुगतने का निर्देश दिया गया।

2. संक्षेप में तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि PW1 गीतिका गुप्ता ने दिनांक 28.08.2013 को थाना कोतवाली रुड़की में एक लिखित प्रतिवेदन (पूर्व का. 1) इस कथन के साथ दिया कि उनके पिता अरुण कुमार गुप्ता, जो कि आई. आई. टी. रुड़की के परिसर में रह रहे थे ,27.08.2013 को रात में गला रेत कर उनकी हत्या कर दी गई थी। घटना की जानकारी उसके चाचा ने दी थी।

3. उक्त रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 28.08.2013 को 16:40 बजे थाना कोतवाली रुड़की में अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया। मामले की जांच की गई और जांच पूरी होने पर अभियुक्त-अपीलार्थी के खिलाफ दिनांक 27.12.2013 को आरोप पत्र (पूर्व का. 12) प्रस्तुत किया गया।

4. धारा 207 Cr.P.C के प्रावधानों का पालन करने के बाद, मामला सत्र न्यायालय के लिए प्रतिबद्ध था।

5. माननीय सत्र न्यायाधीश, हरिद्वार ने दिनांक 25.02.2014 को आईपीसी की धारा 302 के तहत आरोपी-अपीलार्थी के खिलाफ आरोप तय किया, जिस पर आरोपी-अपीलार्थी ने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया और मुकदमा चलाने का दावा किया।

6. अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को साबित करने के लिए PW-1 गीतिका गुप्ता (मुखबिर), PW-2 अल्ताफ, PW-3 चारू, PW-4 कुशा अग्रवाल, PW-5 आई.ओ. एसआई राम कुमार जुयाल, PW-6 कुलदीप सिंह नेगी, PW-7 डॉ. एस.एन. सिंह (जिन्होंने शव परीक्षण किया), PW-8 अरविंद कुमार अग्रवाल, PW-9 वीरेंद्र कुमार गर्ग, PW-10 आईओ इंस्पेक्टर जसवीर सिंह पुंडीर, PW- 11 एसआई प्रदीप तोमर और PW-12 आईओ राजीव रौथन, जिन्होंने जांच पूरी कर चार्जशीट पेश की।

7. इसके बाद, अभियुक्त-अपीलकर्ता का बयान 313 Cr.P.C के तहत दर्ज किया गया था। अभियुक्त-अपीलकर्ता ने झूठा फंसाने का अनुरोध किया और यह भी कहा कि वह निर्दोष है, मृतक ने आत्महत्या की है और पुलिस ने किसी मुखबिर के कहने पर उसे झूठा फंसाया है। बचाव में वह DW-1 मो. आफताफ और DW-2 सुमन के पास गए।

8. रिकॉर्ड पर मौजूद पूरे साक्ष्य की जांच के बाद, ट्रायल कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त-अपीलकर्ता के खिलाफ अपने मामले को पूरी तरह से साबित कर दिया है और तदनुसार यह अभियुक्त-अपीलकर्ता को दोषी ठहराने और सजा देने के लिए आगे बढ़ा, जैसा कि पैरा संख्या 1 में चर्चा की गई है।

9. PW1 गीतिका गुप्ता ने प्रथम सूचना रिपोर्ट के तर्कों का समर्थन किया है और कहा है कि 27.08.2013 को उसे अपने चाचा श्री बी.के. गुप्ता के माध्यम से सूचना मिली कि उसके पिता की गर्दन काटकर हत्या कर दी गई थी और उन्हें जलाने का प्रयास भी किया गया था। जब उसने अपने पिता के मोबाइल नंबर पर फोन किया तो वह स्विच ऑफ मिला। उसके चाचा ने उसे आगे बताया कि उसके पिता का फोन और बटुआ भी गायब है। इन्हीं कथनों के साथ उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की (पूर्व का. 1)|

10. PW-2 अल्ताफ, जिसे वसूली का गवाह कहा जाता है, अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया और पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया।

11. PW-3 चारू मृतक की एक अन्य पुत्री है। उसने अभिसाक्ष्य दिया है कि उसके पिता अपीलार्थी को जब भी बाहर जाते थे साथ ले जाते थे। उसने आगे कहा कि वह अपने पिता से रोजाना बात करती थी। एक दिन उसके पिता ने उसे सूचित किया कि उसने अपीलकर्ता को अपने साथ ले जाना बंद कर दिया है, क्योंकि अपीलकर्ता हमेशा उसके पिता से पैसे की मांग करता था और घरेलू सामानों पर उसकी बुरी नजर थी। 22.08.2013 की घटना के बारे में, उसके पिता द्वारा उसे सूचित किया गया कि अपीलकर्ता जबरन घर

में घुस गया था, जिस पर उसके पिता ने अपीलकर्ता को डांटा कि वह बिना घंटी बजाए कमरे में क्यों आया। फिर, अपीलकर्ता ने अपने पिता से पैसे की मांग की, जिसे उसके पिता ने मना कर दिया। इसके बाद अपीलकर्ता ने उसके पिता को भविष्य में उसे देखने की धमकी दी। अपने पिता की मृत्यु की सूचना मिलने पर वह रुड़की आई, जहां आसपास के लोगों और घरेलू नौकरानी सुमन ने उसे बताया कि उन्होंने घटना के दिन अपीलकर्ता को घर के नीचे देखा था।

12. PW4 कुशा मृतक की एक अन्य पुत्री है। उसने इस तथ्य का भी समर्थन किया है कि अपीलकर्ता को उसके पिता ने ड्राइवर के रूप में नियुक्त किया था और वह दिन में एक से दो बार अपने पिता से बात करती थी। नवंबर, 2012 के महीने में जब वह अपने पिता से मिलने आई, तो उन्होंने उसे सूचित किया कि अपीलकर्ता ने झूठे बहाने से कुछ पैसे लिए हैं और उसके पिता ने पप्पू (अपीलार्थी के भाई) को भविष्य में अपीलकर्ता को न भेजने का भी निर्देश दिया। दिसंबर, 2012 के महीने में उसके पिता उससे मिलने आए, फिर उन्होंने अपीलकर्ता पर कुछ हीरा चोरी करने के संदेह के बारे में भी बताया, अमेरिकी डॉलर उसके पिता ने भी उसे 23 और 25 अगस्त को 22.08.2013 की घटना के बारे में सूचित किया, 2013 को कहा कि अपीलकर्ता बिना बताए घर में घुस गया और उससे पैसे की मांग की। जब उसके पिता ने उसे डांटा कि वह बिना अनुमति के कमरे में क्यों आया, तो अपीलकर्ता ने धमकी दी कि वह उसे नहीं छोड़ेगा। उसके पिता की मृत्यु की सूचना मिलने पर वे रुड़की गए थे, जहां पड़ोसियों ने उसे सूचित किया कि अपीलकर्ता को घटना के दिन घर के नीचे देखा गया था और जब घरेलू नौकरानी सुमन ने अपीलकर्ता से उसकी उपस्थिति का कारण पूछा, तो उसने जवाब दिया कि वह उसके पिता से मिलने आया था।

13. PW-5 एस.आई. राम कुमार जुयाल, जो कि मामले का एक औपचारिक गवाह है, अपीलकर्ता के इशारा करने पर चाकू की बरामदगी के अलावा जांच करने की बात साबित की है।

14. PW-6 कुलदीप सिंह नेगी मृतक के घर से खून से सनी चादर और तकिए के कवर की बरामदगी का गवाह है।

15. PW-7 डॉ. एस.एन. सिंह वह व्यक्ति है जिसने मृतक के शरीर का पोस्टमार्टम किया था। उनके अनुसार, निम्नलिखित मृत्यु-पूर्व चोटें पाई गईं:

(a) दाएं लिंबो वंक्षण क्षेत्र से 13 सेंटीमीटर चौड़ाई टीआरटी के साथ डीप बर्न, बायीं इलियाक रीढ़ तक फैली हुई समान चौड़ाई;

(b) छाती के बाईं ओर 3x1 सेंटीमीटर गहरा छेद वाला घाव, निप्पल से 8 सेंटीमीटर नीचे।

(c) 2X1X2 सेंटीमीटर गहरा छितराया हुआ घाव बाएं पार्श्व सुप्राक्लेविकुलर क्षेत्र।

(d) बाएँ कान के पिन्ना के ठीक नीचे 3X2 सेंटीमीटर चीरा हुआ घाव पेशी गहरा।

(e) गर्दन के पूर्वकाल पहलू पर ट्रेकिआ ट्रांसेक्टिंग ट्रेकिअल न्यूरोमस्कुलर बंडल टीआरटी तक 13X5 सेंटीमीटर गहरा;

(f)दाहिने गाल पर 5x1 सेंटीमीटर का कटा हुआ घाव, तिरछा और लंबवत निर्देशित।

(g) दाहिने कान के लोब्यूल के ठीक नीचे 1x1 सेंटीमीटर का कटा हुआ घाव।

चिकित्सा अधिकारी की राय में मृत्यु का कारण श्वासावरोध तथा मृत्यु पूर्व गले में लगी चोट के कारण रक्तस्राव है।

16. PW-8 अरविंद कुमार अग्रवाल और PW-9 वीरेंद्र कुमार गर्ग औपचारिक गवाह हैं, जिन्होंने जांच रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर साबित किए हैं।

17. PW-10 इंस्पेक्टर जसबीर सिंह पुंडीर केस के दूसरे आईओ हैं। उसने अपराध में प्रयुक्त हथियार और मृतक के मोबाइल फोन, जिसे अपीलकर्ता द्वारा उठाया जाना बताया गया है, की वसूली मेमो तैयार करने के तथ्य को साबित किया है।

18. PW-11 एस.आई. प्रदीद तोमर भी मामले का एक औपचारिक पुलिस गवाह है। शव की बरामदगी के बाद तैयार किए गए कुछ जरूरी दस्तावेजों को तैयार करने के संबंध में उन्होंने साबित किया है।

19. PW-12 एस.आई. राजीव रौथन इस मामले के एक अन्य जांच अधिकारी हैं जिन्होंने जांच करने के तथ्य को भी साबित किया है और उसी के समापन के बाद, उन्होंने आरोप-पत्र (पूर्व का. 13) प्रस्तुत किया|

20. इसके बाद आरोपी का बयान 313 Cr.P.C के तहत दर्ज किया गया। जिसमें उन्होंने दोषी न होने की दलील दी और झूठे आरोप में फंसाने की दलील भी दी। अपीलार्थी की ओर से निम्नलिखित दो गवाहों का परीक्षण किया गया।

21. DW-1 मो. अल्ताफ ने मुख्य रूप से इस तथ्य को साबित किया है कि उसने अपीलकर्ता को 29.09.2013 को कोई मोबाइल फोन नहीं दिया।

22. DW-2 सुमन वह व्यक्ति है जिसको मृतक के घर में घरेलू सहायिका कहा जाता है। उसने कहा है कि उसने अपीलकर्ता को घटना स्थल के पास 27.08.2013 को नहीं देखा। उसके अनुसार जब वह घर के अंदर आई तो मृतक मुंह के बल लेटा हुआ था और उसकी पीठ में आग लग गई थी। उसने पानी लाकर आग बुझाई।

23. हमने पक्षकारों के अधिवक्ता को सुना है और न्यायालय की फाइल में उपलब्ध समस्त साक्ष्यों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया है।

24. अपीलकर्ता के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि दृश्य का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। पुलिस पार्टी ने आरोपी का प्रकटीकरण बयान दर्ज नहीं किया, तदनुसार, अपीलकर्ता द्वारा एक चाकू और दो मोबाइल फोन के संबंध में कथित रूप से की गई वसूली अप्रासंगिक है।

25. प्रति कॉन्ट्रा माननीय उप महाधिवक्ता ने राज्य के लिए उपस्थित होकर तर्क दिया कि अपीलकर्ता को दोषी ठहराने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सबूत हैं, और आक्षेपित निर्णय में कोई अवैधता नहीं है।

26. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, घटना 27.08.2013 को हुई थी। PW-1 गीतिका ने घटना की सूचना अपने चाचा से प्राप्त की तथा तदनुसार उसने दिनांक 28.08.2013 को पुलिस थाने में सूचना प्रस्तुत की। उसके बयान के अनुसार, उसने घटना नहीं देखी।

27. PW3 चारू और PW-4 ख़ुशा, जो मृतक की बेटियाँ भी हैं, घटना के समय विदेश में थीं, जिससे पता चलता है कि तीनों बेटियाँ PW-1 गीतिका, PW-3 चारू और PW-4 खुशा घटना के स्थान पर नहीं थीं घटना।

28. PW4 कुशा, श्रीमती के बयान के अनुसार। सुमन मृतक की रसोइया थी, जो हमेशा मृतक के घर खाना बनाने आती थी और अपीलकर्ता को सुमन ने देखा था जो 27.08.2013 को मृतक के कमरे से नीचे आ रही थी, लेकिन उसे पेश नहीं किया गया था। अभियोजन पक्ष की बजाय उसकी DW-2 के रूप में जांच की गई और उसने स्पष्ट रूप से कहा कि उसने अपीलकर्ता को 27.08.2013 को मृतक के घर पर नहीं देखा।

29. अभियोजन पक्ष की यह कहानी है कि अपीलकर्ता ने अपना अपराध कबूल किया और उसके द्वारा चाकू (अपराध में प्रयुक्त) की ओर इशारा करने पर मृतक से संबंधित दो मोबाइल फोन बरामद किए गए।

30. रिकवरी मेमो पूर्व. का 4 रिकॉर्ड पर है। रिकवरी मेमो के अनुसार, वसूली के समय अल्ताफ और महताब (सार्वजनिक गवाह) भी मौजूद थे|

31. अभियोजन पक्ष ने PW-2 के रूप में अल्ताफ को पेश किया, लेकिन उसने वसूली का समर्थन नहीं किया, जबकि अन्य गवाह मेहताब को अभियोजन पक्ष द्वारा पेश नहीं किया गया।

32. यह ध्यान रखना बहुत प्रासंगिक है कि यह अभियोजन पक्ष का मामला है कि अपीलकर्ता को गिरफ्तार किया गया था और उसने पुलिस के सामने खुलासा किया कि उसने अपराध किया था और वह चाकू (अपराध में

प्रयुक्त) बरामद कर सकता है और साथ ही संबंधित मोबाइल फोन भी बरामद कर सकता है। मृतक को। इस प्रकार, अपीलकर्ता के इंगित करने पर, उपरोक्त सामान (चाकू और दो मोबाइल) बरामद किए गए, लेकिन जांच अधिकारी ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 26 के तहत परिकल्पित उनके बयान को दर्ज नहीं किया। चूंकि साक्ष्य अधिनियम की धारा 26 के तहत कोई प्रकटीकरण बयान दर्ज नहीं किया गया था, तदनुसार, साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अनुसार वसूली संदिग्ध हो जाती है। हालांकि, वसूली को साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के अनुसार अभियुक्त के आचरण के आलोक में देखा जा सकता है यदि ऐसा आचरण किसी भी तथ्य या प्रासंगिक तथ्य को प्रभावित करता है , लेकिन, यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि चाकू पर मिले खून के धब्बे मृतक से संबंधित थे या मोबाइल फोन भी मृतक से संबंधित थे।

33. जहां तक दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील का संबंध है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पदम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2000) 1 SCC 621 में अपीलीय न्यायालय के कर्तव्य पर विचार करते हुए अभिव्यक्त किया है कि:-

"2… अपीलकर्ता अदालत का यह कर्तव्य है कि वह मामले में जोड़े गए सबूतों को देखे और एक स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंचे कि क्या उक्त सबूतों पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं और अगर इस पर भरोसा किया जा सकता है, तो क्या अभियोजन पक्ष के खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है। उक्त साक्ष्य पर युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध होना कहा गया है। सिद्ध और स्वीकृत तथ्यों से निष्कर्ष निकालने में एक गवाह की विश्वसनीयता को अपीलीय अदालत द्वारा आंका जाना चाहिए। यह याद रखना चाहिए कि निचली अदालत की तरह अपीलीय अदालत को

सकारात्मक रूप से संतुष्ट होना होगा कि अभियोजन का मामला काफी हद तक सही है और आरोपी का दोष सभी उचित संदेह से परे साबित हो गया है क्योंकि निर्दोषता की धारणा जिसके साथ आरोपी शुरू होता है, तब तक जारी रहता है जब तक कि उसे अपील के अंतिम न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया जाता है और यह अनुमान न तो बरी होने से मजबूत होता है और न ही ट्रायल कोर्ट में सजा से कमजोर होता है।

34. इसी तरह, **रामा बनाम राजस्थान राज्य में, (2002) 4 SCC 571** में रिपोर्ट किया गया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपीलीय अदालत पर निम्नलिखित शब्दों में कर्तव्य लगाया है: -

"4...........यह अच्छी तरह से तय है कि एक आपराधिक अपील में, अपीलीय अदालत को सबूतों का पुनर्मूल्यांकन करने का कर्तव्य सौंपा गया है और यह अकेले ट्रायल कोर्ट द्वारा सबूतों के मूल्यांकन पर अपील का निपटान करने के लिए आगे नहीं बढ़ सकता है, खासकर तब जब अपील पहले ही स्वीकार कर ली गई हो और अंतिम सुनवाई के लिए रखी गई हो| इस तरह की प्रक्रिया को कायम रखना किसी अभियुक्त के अपील के मूल्यवान अधिकार को नकारने जैसा होगा, जिसकी कानून के तहत अनुमति नहीं दी जा सकती है।"

35. इसके अलावा, मज्जल बनाम हरियाणा राज्य (2013) 6 SSC 798 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ ने इस प्रकार फैसला सुनाया: -

"7. उच्च न्यायालय के लिए यह विचार करना आवश्यक था कि क्या निचली अदालत के साक्ष्य का आकलन और उसकी राय कि अपीलकर्ता को दोषी ठहराया जाना चाहिए, पुष्टि करने के योग्य है या नहीं। यह कवायद इसलिए जरूरी है क्योंकि दोषसिद्धि के कारण अभियुक्त की व्यक्तिगत स्वतंत्रता कम हो जाती है। उच्च न्यायालय को अपने कारण बताना चाहिए कि वह रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य को क्यों स्वीकार कर रहा है। विचारण न्यायालय के दृष्टिकोण से उच्च न्यायालय की सहमति तभी स्वीकार्य होगी जब वह कारणों से समर्थित हो। ऐसी अपीलों में यह प्रथम अपील की अदालत है। कारण गूढ़ नहीं हो सकते। इससे हमारा तात्पर्य यह नहीं है कि उच्च न्यायालय से अनावश्यक रूप से लंबा ग्रंथ लिखने की अपेक्षा की जाती है। निर्णय छोटा हो सकता है लेकिन महत्वपूर्ण सबूतों और महत्वपूर्ण प्रस्तुतियों के लिए दिमाग के उचित आवेदन को प्रतिबिंबित करना चाहिए जो मामले की जड़ तक जाते हैं।"

36. इस समय, "**शरद बिर्धीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य**" के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर ध्यान देना प्रासंगिक है, जिसकी रिपोर्ट **(1984) 4 SCC पृष्ठ 116** में दी गई है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर एक मामले में साक्ष्य की सराहना के पांच सुनहरे सिद्धांत निर्धारित किए हैं। वे इस प्रकार हैं:

(a). "जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए। संबंधित परिस्थितियाँ "चाहिए" या " अवश्य " और न कि "हो सकता है" स्थापित;

(b) इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के दोष की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए, अर्थात अभियुक्त के दोषी होने के अलावा उन्हें किसी अन्य परिकल्पना पर स्पष्ट नहीं किया जाना चाहिए;

(c) परिस्थितियाँ एक निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए;

(d) उन्हें सिद्ध की जाने वाली परिकल्पना को छोड़कर हर संभव परिकल्पना को बाहर कर देना चाहिए; और

(e) साक्ष्य की एक श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि अभियुक्त की बेगुनाही के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न छोड़े और यह दर्शाए कि सभी मानवीय संभावना में अभियुक्त द्वारा कार्य किया जाना चाहिए।

37. परिस्थितिजन्य साक्ष्य का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जिस परिस्थिति से अपराधबोध का निष्कर्ष निकाला जाना है, वह पूरी तरह से स्थापित होनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने आगे माना है कि संबंधित परिस्थिति 'चाहिए या होनी चाहिए' और 'नहीं' 'हो सकती है'। दूसरे शब्दों में, अभियोजन पक्ष, पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामले में, परिस्थिति को निर्णायक रूप से स्थापित करना चाहिए।

38. परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर मामले में, यदि अभियोजन द्वारा स्थापित की जाने वाली परिस्थितियों की श्रृंखला स्थापित नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में अभियुक्त को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

39. जहां तक मृतक से संबंधित उन दो मोबाइल फोनों का संबंध है, उन मोबाइल फोनों की पहचान मृतक के परिवार के किसी सदस्य द्वारा नहीं की गई थी। यहां तक कि उन मोबाइलों में भी सिम कार्ड नहीं लगा था और न ही उनकी इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी (IMEI) साबित हुई थी. रिकॉर्ड पर ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह पता चले कि वे दोनों मोबाइल फोन मृतक से संबंधित थे।

40. यद्यपि एफएसएल रिपोर्ट के अनुसार चाकू पर खून पाया गया था लेकिन अभियोजन पक्ष द्वारा कोई पुख्ता या विश्वसनीय साक्ष्य जोड़कर यह साबित नहीं किया गया है कि चाकू पर मिले खून का संबंध मृतक से था।

41. PW-3 चारू और PW-4 खुशा के बयानों के अनुसार, एक समय पहले आरोपी मृतक के घर में घुस गया और पैसे की मांग की। जब मृतक ने इसके लिए मना कर दिया, तो अपीलकर्ता-आरोपी ने उसे भविष्य में देख लेने की धमकी दी, लेकिन उन गवाहों (PW3 और PW4) ने मुखबिर PW-1 गीतिका, जो मृतक की एक और बेटी भी है, को इस तथ्य का खुलासा नहीं किया। मृतक के बेहद करीबी नौकर कुछ नहीं बोले। यहाँ तक कि मृतक का बड़ा भाई, जो उसी आस-पास रहता था, ने भी मृतक के उद्देश्य के बारे में कुछ नहीं कहा और न ही उसने PW-1 गीतिका को उक्त माँग तथा अपीलार्थी द्वारा दी गई धमकी के बारे में सूचित किया।

42. उपर्युक्त चर्चा से निम्नलिखित बातें उभरकर सामने आती हैं:-

(a) अपीलकर्ता का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है।

(b) अपीलकर्ता के खिलाफ दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट में कोई मकसद नहीं है।

(c) घटनास्थल का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है।

(d) अभियोजन कहानी के अनुसार, महिला रसोइया सुमन ने 27.08.2013 को मृतक के घर से नीचे आते समय अपीलकर्ता को देखा, लेकिन जब वह बचाव पक्ष की गवाह के रूप में पेश हुई, तो वह स्पष्ट रूप से उपरोक्त तथ्यों से मुकर गई।

(e) चाकू और मोबाइल की बरामदगी से पहले आईओ द्वारा कोई खुलासा बयान दर्ज नहीं किया गया था।

(f) मृतक के मोबाइल में कोई सिम कार्ड नहीं मिला।

(g) मृतक के परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा मोबाइल फोन की पहचान नहीं की गई थी।

(h) ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे पता चले कि दोनों मोबाइल मृतक से संबंधित थे।

(i) साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के मद्देनजर अपीलकर्ता के कहने पर की गई वसूली भी संदिग्ध है।

(j) यहां तक कि अभियोग द्वारा कथित अपराध करने के लिए अपीलकर्ता के विरुद्ध कोई मनःस्थिति भी आरोपित नहीं की जा सकी।

(k) अभियोजन पक्ष अपीलकर्ता को कथित अपराध से जोड़ने के लिए कोई लिंक सबूत नहीं दे सका।

43. हमने ट्रायल कोर्ट के समक्ष अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में पूरे साक्ष्य का पूरी तरह से अध्ययन किया है और उसका पुनर्मूल्यांकन किया है। ऐसा

करने पर, हम पाते हैं कि अभियोजन अपीलकर्ता के खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सका। विचारण न्यायालय ने केवल हत्या के हथियार और मोबाइल फोन की बरामदगी के आधार पर अपीलकर्ता को दोषी ठहराया, हालांकि, हमारे द्वारा यहां ऊपर की गई चर्चा से, हम पाते हैं कि विचारण न्यायाधीश ने सजा का निष्कर्ष दर्ज करते समय गलती की है|

44. कानून अच्छी तरह से स्थापित है कि प्रत्येक और हर आपत्तिजनक परिस्थिति को विश्वसनीय और ठोस साक्ष्य द्वारा स्पष्ट रूप से स्थापित किया जाना चाहिए और इस तरह साबित की गई परिस्थितियों को घटनाओं की एक श्रृंखला बनानी चाहिए जिससे अभियुक्त के अपराध के बारे में एकमात्र अनूठा निष्कर्ष सुरक्षित रूप से निकाला जा सके और दोष के विरुद्ध कोई अन्य परिकल्पना संभव नहीं है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर काफी हद तक निर्भर रहने वाले मामले में हमेशा एक खतरा होता है कि अनुमान या संदेह कानूनी सबूत का स्थान ले सकता है। न्यायालय, कानून के स्थापित सिद्धांतों के प्रति सावधानी बरतते हुए कि इस तरह के मामले में, जहां अभियोजन परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर निर्भर है, अभियोजन पक्ष को सभी आवश्यक परिस्थितियों को रखना और साबित करना होगा, जो बिना किसी झंझट के एक पूरी श्रृंखला का गठन करेगा। और इस परिकल्पना की ओर इशारा करते हुए कि अभियुक्त के अलावा किसी ने अपराध नहीं किया था, जिसे वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष साबित करने में विफल रहा है।

45. इस प्रकार, उपरोक्त चर्चा से, हमें यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि अभियोजन पक्ष अपीलकर्ता के खिलाफ अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह से विफल रहा है। अभियोजन पक्ष द्वारा बताई गई परिस्थितियाँ भी, विशेष रूप से अपीलकर्ता के दोष की ओर

इशारा करने वाली परिस्थितियों की श्रृंखला को पूरा नहीं करती हैं। इस मामले को देखते हुए, हमारा दृढ़ मत है कि अभियोजन के मामले में एक उचित संदेह है और उपरोक्त साक्ष्य के आधार पर अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को बरकरार रखना उचित या न्यायोचित नहीं है।

46. परिणाम में, अपील स्वीकार की जाती है। निचली अदालत द्वारा आई०पी०सी की धारा 302 के तहत दर्ज अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को रद्द किया जाता है। इस अपराध के लिए अपीलकर्ता को दी गई सजा भी रद्द की जाती है। अपीलकर्ता को अपराध से बरी किया जाता है। अपीलकर्ता जेल में है, तदनुसार, यदि किसी अन्य मामले में उसकी आवश्यकता नहीं है, तो उसे तत्काल रिहा किया जाए।

47. एल०सी०आर के साथ इस फैसले और आदेश की एक प्रति संबंधित न्यायालय को तत्काल भेजी जाए।

48. रजिस्ट्रार न्यायिक को भी निर्देशित किया जाता है कि वह इस निर्णय की एक प्रति तत्काल पालना हेतु जेल प्राधिकरण को भिजवायें।

संजय कुमार मिश्रा, ए.सी.जे.

रमेश चंद्र खुल्बे, जे.